Mr. Speaker: Next question.

Shri Bade: This is important because the States have decided to proceed on the basis of caste and not on economic considerations.

Mr. Speaker: I know that everything that comes from the hon. Member is important, but sometimes I cannot accommodate him.

Shri Sonavane: This is an important question regarding the backward classes....

Mr. Speaker: I know. Therefore, I have passed on to the next question.

Universities in Third Five Year Plan

\+

*217. **Shri Raghunath Singh:**
Shri Daji:
Shri A. V. Raghavan:
Shri Subbaraman:
Shri Maruthiah:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Hem Raj:
Maharajkumar Vijaya Ananda:
Shri Mohsin:
Shri Umanath:
Shri Ram Ratan Gupta:
Shri K. Pattnayak:
Shri Karjee:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) how many universities were proposed to be started during the Third Five Year Plan period;

(b) the total allocation therefor;

(c) how many of them have started;

(d) how many have been sanctioned; and

(e) how many are under consideration?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*See* Appendix I, annexure No. 64].

(c) Five.

(d) and (e). It is for the State Governments concerned to establish new Universities within their jurisdiction.

श्री रघुनाथ सिंह : किन-किन राज्य सरकारों ने कितनी-कितनी युनिवरसिटियों की स्थापना के वास्ते आपसे प्रार्थना की है और उन्होंने कितना रुपया मांगा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसाकि मैं ने स्टेटमेंट में बताया यह पांच यूनिवरसिटियां तो स्थापित हो चुकी हैं—बिहार में एक, पंजाब में एक, राजस्थान में एक और वैस्ट बंगाल में दो । अभी हाल में मध्य प्रदेश की युनिवरसिटीज के लिये भी मंजूरी दे दी गई है । तीन युनिवरसिटियां वहां स्थापित होने का प्रस्ताव है—ग्वालियर, इंदौर और रायपुर में ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जितने विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय किया था इस स्टेटमेंट को देखने से यह प्रतीत होता है कि आगामी वर्ष में उन की संख्या बढ़ जायेगी तो क्या इस सम्बन्ध में भी शिक्षा मंत्रालय ने कुछ निश्चय किया है कि जितना निश्चय आरम्भ में किया था उतनी ही संख्या रहनी है या उस में कुछ वृद्धि की जायगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रश्न के उत्तर में मुझे यह निवेदन करना है कि जब योजना बनी थी उस वक्त राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव मांगे थे और उन्हीं के आधार पर यह सारा नकशा बनाया गया था । अब यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वह और नई युनिवरसिटीज कितनी खोलना चाहते हैं क्योंकि जिम्मेदारी इस विषय में राज्य सरकारों की है । केन्द्रीय सरकार से कोई आर्थिक सहायता नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये नहीं दी जाती है ।

Mr. Speaker: Shri Venkatasubbaiah.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं ने भिन्न प्रश्न पूछा था । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : आखिर में मैं आप को दुबारा इजाजत दे दूंगा ।

Shri Venkatasubbaiah: May I know whether any proposal has been received from the Andhra Pradesh Government for establishing a university in that area?

Dr. K. L. Shrimali: I may draw the attention of the hon. Member to the statement which I have laid on the Table of the House. Andhra Pradesh has a proposal to start one university.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा मंत्रालय ने कुछ संख्या निर्धारित की थी कि आगामी पांच वर्षों में सारे देश में इतने विश्वविद्यालय खोले जायेंगे लेकिन इस स्टेट्मेंट को देखने से प्रतीत होता है कि उतनी संख्या से ज्यादा बढ़ गये हैं तो अभी जो बाकी वर्ष शेष रह जाते हैं उन में विश्वविद्यालय खोलने की गुंजाइश रहेगी तो इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय ने क्या निर्णय किया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं समझता हूं कि मैंने जो उत्तर दिया है उसको वे अच्छी तरह समझे नहीं हैं जो इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं । जो योजना बनी थी ....

अध्यक्ष महोदय : अगर दोनों एक तरीके से न समझे तो मैं क्या करूं ? उन को भी यह शिकायत है कि आप उनके प्रश्न को नहीं समझे हैं और आप की शिकायत यह है कि आप ने जो जवाब दिया वह उन्होंने अच्छी तरह नहीं समझा है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मार्ग प्रदर्शन तो आप से ही मिल सकता है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि मैं समझा नहीं सका ।

डा० का० ला० श्रीमाली : संभव है मेरी गलती हो मैं एक बार फिर प्रयत्न करता हूं । तृतीय पंचवर्षीय योजना राज्य सरकारों के साथ बैठ कर बनी थी । उन्होंने जैसा प्रस्ताव किया और जो उस वक्त आवश्यकता उन की थी उस को देख कर इस स्टेटमेंट के मुताबिक १६ यूनिवरसिटीज़ खोलने की एक योजना बनाई थी । अब परिस्थिति यह है कि जहां तक नये विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है भारत सरकार से कोई साहयता नहीं मिली है और न ही युनिवरसिटी ग्रान्ट्स कमिशन नये विश्वविद्यालय खोलने के लिये कोई सहायता देता है लेकिन जैसे-जैसे राज्य सरकारों के प्रस्ताव आते जाते हैं वैसे-वैसे उनकी जांच की जाती है । यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमिशन उन को मशविरा देता है और फिर जिम्मेदारी उन की है उन कि वह नये विश्वविद्यालय खोलें । अगर राज्य सरकारों के पास से हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो इस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं । यह उन्ही की जिम्मेदारी है और उन को ही पूरी करनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं समझता हूं वह यह कि जो संख्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय खोलने की थी उन से अधिक खुल गये । जो बाकी रह गये हैं और अभी नहीं खुले हैं उन का पंचवर्षीय में क्या बनेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह नतीजा कैसे निकाला? १६ नये विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव था । अभी मैंने निवेदन किया कुल पांच ही खुले हैं तो १६ और ५ में तो काफी फर्क है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां बहुत फर्क है ।

Shri A. P. Jain: Is there a proposal to start any federal universities; if so, may I know their number and the progress that has been made?

Dr. K. L. Shrimali: With regard to federal universities, I am afraid there is some confusion. The University Grants Commission in its recent report has suggested that there should be one federal type of university in each State. The Delhi University is a federal type of university. A federal type of university is a little different from the other type of university, for example a residential university, and it is suggested that there should be one federal university in each State. If the hon. Member is asking that there should be a Central university....

Shri A. P. Jain: I never mentioned Central university. I asked: how many federal universities are proposed to be set up, and what is the progress?

Dr. K. L. Shrimali: The University Grants Commission has suggested that there should be one federal type of university in each State.

Shri P. K. Deo: In the long list of 19 universities in the statement, even though there has been allocation of funds for various universities, I do not find any allocation of funds for the solitary university in my State, that is Orissa. Secondly, I want to know whether any decision has been taken to have a university in Sambalpur.

Mr. Speaker: We cannot go into details in this question.

Shri Hem Barua: Is it a fact that the Kothari committee appointed by the University Grants Commission had suggested that each university should select some subject for specialised training up to the international standard? If so, what is the reaction of Government to this and do Government propose to translate this into action?

Mr. Speaker: This is another matter of detail.

Shri Mohammad Elias: I find from the statement that Rs. 225 lakhs have been sanctioned for West Bengal. In view of the serious educational problem in West Bengal....

Mr. Speaker: I would not like to go into all such details at this moment.

Shri S. M. Banerjee: The figures are given there in the statement.

Mr. Speaker: The number and allocation was wanted here.

Shri S. M. Banerjee: I want to know from the hon. Minister if these universities in U.P. are likely to be established....

Mr. Speaker: If I did not allow any question for West Bengal how can I allow for U.P.? (*Interruption*). I do not want to go into details.

श्री राम सेवक यादव: शिक्षा मंत्री ने अभी बताया कि पांच विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई है, जब कि स्टेटमेंट में १६ युनिवर्सिटीज दी गई हैं, तो १४ युनिवर्सिटीज के खुलने में क्या दिक्कत है ?

Mr. Speaker: Order, order. I will not allow this. Hon. Members go on repeating the same question for one State or the other. Shri Harish Chandra Mathur.

Shri Harish Chandra Mathur: How will the hon. Minister explain the disparity in allocation. There are Rs. 50 lakhs allotted for Maharashtra, one university, Rs. 10 lakhs only for Rajasthan; Rs. 225 lakhs for two universities in West Bengal and for M.P. for three, only Rs. 20 lakhs. Is it that the backward States get much less?

Dr. K. L. Shrimali: These allocations have been made in accordance with the needs and requirements of the particular State.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस का क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में तीन विश्वविद्यालय खोलने के लिये ८७ लाख रुपये लेकिन वैसट बंगाल में दो विश्वविद्यालय खोलने के लिये २२५ लाख रुपये की मंजूरी दी गयी है :

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वैश्चन । श्री हंसदा ।

श्री म० ला० दिवेदी : मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने खुद कहा है कि उत्तर न दिया जाये ।

डा० गोविंद दास : अध्यक्ष महोदय, एक जरूरी सवाल पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बदकिस्मती है कि मैं अगले सवाल पर चला गया हूं ।

Manufacture of Helicopters

\+

*218. **Shri Subodh Hansda:**
Shri Basumatari:
Shri S. C. Samanta:
Shri G. K. Singha:
Shri Bhakt Darshan:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement has been signed with a French firm to manufacture Helicopters in India at Kanpur and Bangalore;

(b) if so, the terms of the contracts;

(c) whether all components of the Helicopters will be manufactured or only the spare parts; and

(d) how long it will take to manufacture the entire engine and its components?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Raghuramaiah): (a) An agreement has been signed with a French firm for the manufacture in India of this helicopter. The engine for this helicopter is manufactured by a different firm and the above agreement excludes the manufacture of the engine.

(b) It will not be in the public interest to disclose the details of the terms of the contract; it may however, be stated that we shall be paying only a reasonable licence fee on convenient terms of payment. There will be no payment on account of royalties.

(c) All components of the helicopter and not only spare parts will be taken up progressively for manufacture in India.

(d) Negotiations are in progress for the conclusion of an agreement to manufacture the engine in India.

Shri Hem Barua: This is not a defence matter. I want to raise a point of order. They are going to manufacture helicopters in this country. There has been so much of work on this matter. Is it that the terms cannot be disclosed in public interest? I cannot understand this. The agreement is entered into; the manufacture would follow the pattern of that agreement and everything else. But the Government would not disclose the details.

Mr. Speaker: He has disclosed as much as he thought he could possibly do. But, other details, he says, it is not in public interest to give further. He has given some facts. But if the hon. Member puts in any question and the answer is denied I can see whether I can interfere.

The Minister of Defence (Shri Krishna Menon): Probably, the hon. Member wants to know all the details that are given in the agreement. I think the Government also has got some responsibilities in this matter; the agreement contains the quantum and the rate of production and the rate of Indianisation and the various other restrictive clauses. That is one point. Secondly, it is concluded with a foreign firm which is usually tied up with the Government of that country and if these things are discussed in this way, then it makes it impossible to obtain favourable terms;